भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 167
(जिसका उत्तर सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

देश में मुद्रास्फीति

167. डॉ. के सुधाकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्तमान मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्षित दायरे के अंतर्गत बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग सहित भारतीय बैंकिंग क्षेत्र प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में किसानों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट रेटिंग अवसंरचना संबंधी ब्यौरा और उसकी स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलयन करने और समेकन की योजना बना रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और 2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर) में 1.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि 1.9 प्रतिशत की मौजूदा खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड (±2 प्रतिशत अंकों के टोलरेंस बैंड के साथ 4 प्रतिशत) के 2 प्रतिशत की निम्नतर सीमा से मामूली नीचे है, तथापि आरबीआई का अनुमान है कि 2025-26 के लिए वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत होगी, जो इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड के भीतर है। आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य बैंड के भीतर संरेखित करने के लिए, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2025 से संचयी रूप से नीतिगत दर में 100 आधार अंकों की कमी की है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आम नागरिक पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और व्यापार नीति सहित कई प्रशासनिक उपाय भी किए हैं। इनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि, खुले बाजार में खरीदे गए अनाजों की रणनीतिक बिक्री, कम आपूर्ति की अवधि के दौरान आयात और निर्यात पर अंकुश लगाने की सुविधा, चुनिंदा वस्तुओं की बाजार में अधिक आपूर्ति करने के लिए स्टॉक सीमा का कार्यान्वयन, रियायती दरों पर भारत ब्रांड के तहत चुनिंदा खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री, जल्दी खराब होने वाली बागवानी और कृषि वस्तुओं के लिए बाजार में हस्तक्षेप, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण और सबसे बढ़कर, आयकर से ₹12 लाख (और मानक कटौती वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख) तक की वार्षिक आय को छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि करना और माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों के हालिया युक्तिकरण के माध्यम से उपभोग की मांग को बढ़ावा देना।

(ग) : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए, आरबीआई ने अपने विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे के माध्यम से, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन, डेटा एनालिटिक्स और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) संचालित सेवाओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर अभिनव उत्पादों और समाधानों के परीक्षण को सक्षम किया है। खुदरा भुगतान, सीमा पार भुगतान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण, वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन और एक थीम-न्यूट्रल समूह जैसे विषयों के तहत पांच समूह पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (फ्री-एआई) की जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति ने 13 अगस्त, 2025 को अपनी रिपोर्ट में संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इस क्षेत्र को जिम्मेदारी से एआई का लाभ उठाने में मदद करने के लिए दिशानिर्देशों को रेखांकित किया।

(घ) : केंद्रीय बजट 2025-26 में, माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और अन्य ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) ढांचे के विकास की घोषणा की। सभी चार ऋण सूचना कंपनियों ने मालिकाना स्कोरिंग मॉडल तैयार किए हैं, जिनका वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा उनकी सटीकता और तकनीकी मजबूती का आकलन करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

****